

अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष-2023

भारतीय प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में अनुमोदन का सफरनामा

एस.के. मल्होत्रा*

"संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करता है कि आम लोगों के पास उच्च गुणवत्ता वाले पर्याप्त आहार की नियमित पहुंच हो। कृषि समिति (सीओएजी) एफएओ के शासी निकायों में से एक है, जो कृषि मुद्दों पर समग्र नीति और नियामक मार्गदर्शन प्रदान करती है। सीओएजी वैश्विक कृषि नीति, नियामक मामलों पर एफएओ सम्मेलन, इस संगठन की प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों एवं बजट से संबंधित मामलों पर एफएओ परिषद को सलाह और सिफारिशें भी प्रदान करता है। सीओएजी की स्थापना 1971 में हुई थी और इसके 130 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। ये सदस्य आमतौर पर हर दो साल में मिलते हैं, जो कृषि समिति के विचाराधीन कृषि और आहार पोषण से संबंधित विशिष्ट मामलों की समीक्षा करते हैं।"



वर्ष 2018 के जुलाई माह में भारत को एफएओ, रोम, इटली में 1-5 अक्टूबर, 2018 को होने वाली कृषि पर बैठक की एफएओ की समिति के 26वें सत्र में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला था। भारत सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी दी जिसमें, डा. एस.के. मल्होत्रा, तत्कालीन कृषि आयुक्त इस प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और डा. एस.के. चौधरी, तत्कालीन सहायक महानिदेशक (मृदा और जल प्रबंधन) एवं अब भाकृअनुप के उप महानिदेशक (एनआरएम) सदस्य थे। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में परामर्श के बाद पहल की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। इस मद को एफएओ के एजेंडे में शामिल करने के लिए एफएओ की कृषि समिति के सचिव, डा. रॉबर्ट जी. गुई के साथ डा. अलका भार्गव, जेएस (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) और सुश्री रीनत संधू, राजदूत ईओआई, रोम के माध्यम से भी उठाया गया। एफएओ इस प्रस्ताव के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री से अनुरोध की अपेक्षा रखता था। इसके बाद कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस प्रस्ताव पर आधारित माननीय कृषि मंत्री के कार्यालय से अनुरोध पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2018 को भेजा गया, जो श्री जोस ग्राजियानो दा सिल्वा, महानिदेशक, एफएओ को संबोधित किया गया था (लेख में पत्र की प्रति संलग्न)। इस पत्र के जवाब में, एफएओ ने संबंधित डिवीजन द्वारा पूरी तरह से जांच करने के बाद, इस प्रस्ताव को पहले से परिचालित एजेंडे में, अतिरिक्त रूप से, बाद के चरण में शामिल करने के लिए स्वीकार किया गया था। इसके साथ ही महानिदेशक, एफएओ द्वारा श्री राधा मोहन सिंह, तत्कालीन केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार को एक पत्र भेजकर इसे शामिल करने की पुष्टि की गई थी।

*परियोजना निदेशक, भाकृअनुप-कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, दिल्ली एवं पूर्व कृषि आयुक्त, भारत सरकार

कृषि समिति के 26वें सत्र की रिपोर्ट के अंश

(अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष 2023)

1. कृषि समिति का 26वां सत्र 1-5 अक्टूबर 2018 को एफएओ रोम में आयोजित किया गया। डा. एस.के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डा. एस.के. चौधरी, एडीजी (एसडब्ल्यूएम), आईसीएआर ने कार्यवाही में भाग लिया। अधोहस्ताक्षरी भी अधिकांश सत्रों में उपस्थित थे।
2. एजेंडा मद 4.6 में अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के लिए प्रस्ताव भारत के आग्रह पर शामिल किया गया था। अक्टूबर 2018 की दोपहर को यह चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। अन्य एजेंडा मदों के विपरीत, जो एफएओ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये, भारत को यह प्रस्ताव/मद पेश करने का विशेषाधिकार दिया गया था। डा. एस.के. मल्होत्रा ने पौष्टिक अनाजों और इनकी पोषण गुणवत्ता पर एक विस्तृत पॉवरपांइट प्रस्तुति (मंच से) दी। इसमें उन्होंने सीमांत किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में इन पौष्टिक अनाजों की अनुकूलता के महत्व पर भी चर्चा की।
3. प्रात:कालीन सत्र में चर्चा के दौरान कार्यसूची मद संख्या 4.4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के लिए चिली द्वारा रखे गए प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी गई कि इस प्रस्ताव को पहले 2023 के लिए आवंटित किया गया था और बाद में इसे 2021 में स्थानांतरित किया गया।
4. इससे हमें एक अवसर मिला और डा. मल्होत्रा ने अपनी प्रस्तुति के अंत में अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष को वर्ष 2026 के बदले वर्ष 2023 में आयोजित करने के संबंध में कृषि समिति से आग्रह किया। सुश्री मार्सेला विल्लरियल एफएओ (जो आईवाईएम की नोडल अधिकारी हैं) निदेशक, भागीदारी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग प्रभाग, एफएओ द्वारा उल्लेख किया कि जब तक पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, एफएओ को ऐसा करने में प्रसन्नता होगी।
   डा. मल्होत्रा की प्रस्तुति के बाद डा. हंस ड्रेयर, निदेशक, पौध उत्पादन और संरक्षण प्रभाग, एफएओ, जिन्होंने कृषि समिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष हेतु सार तैयार किया था, ने पौष्टिक अनाजों की उपयोगिता के साथ इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला।
5. जब यह मंच टिप्पणियों के लिए खोला गया तब माली के प्रतिनिधि, जो अफ्रीकी गणराज्य समूह की ओर से बोल रहे थे, ने हमारे प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के आयोजन से विशेष रूप से लाभ होगा, जिनमें छोटे किसान अधिक लाभान्वित होंगे। नाइजीरियाई राजदूत ने भारत की पहल का समर्थन करते हुए विस्तार से बात रखते हुए कहा कि इन फसलों के फलने-फूलने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए और यह तीनों मुख्य फसलों जैसे-चावल, गेहूं और मक्का के लिए वास्तविक चुनौती होगी। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने भारत का धन्यवाद किया। चीन की ओर से भी भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया और पौष्टिक अनाजों के महत्व को रेखांकित किया। इस क्रम में यह भी कहा गया कि परंपरागत रूप से पौष्टिक अनाजों का व्यापक रूप से उत्तरी चीनी प्रांतों (जीआईएएचएस) में उत्पादन किया जाता रहा है। जिम्बाब्वे, इथियोपिया, एरिस्ट्रिया, सेनेमल और रूस ने भी हमारे प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन किया। ऑस्ट्रिया (यूरोपीय संघ की ओर से) ने कहा कि वे पौष्टिक अनाजों के पोषण संबंधी लाभों को स्वीकार करते हैं और भारतीय प्रस्ताव का स्वागत करते हैं।
6. गहन विचार-विमर्श के बाद, कृषि समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के लिए हमारे प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। **कृषि समिति की स्वीकृत रिपोर्ट** (जिसे अंतिम दिन अपनाया गया था) में इसका उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया:
   "पौष्टिक अनाजों के पोषण महत्व और पारिस्थितिक लाभों को उपभोक्ताओं, उत्पादकों और नीति-निर्माताओं तक पहुंचाने के साथ इनके उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और खपत में सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पारिवारिक कृषि दशक को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय पोषक आहार वर्ष 2023 के प्रस्ताव का अनुमोदन असाधारण आधार पर किया गया। मसौदा सम्मेलन संकल्प के लिए प्रस्तुत किया जाना है, जिसे एफएओ सम्मेलन के 41वें सत्र की 160वीं परिषद बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।
   जानकारी और रिकॉर्ड के लिए।

आर. रमेश
अटैशे (कृषि)

भारत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को शामिल करने तथा सीओएजी में चर्चा के लिए अनुमोदन मिलने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के लिए निर्धारित व्यापक उद्देश्यों के साथ पृष्ठभूमि, पोषण, अधिकतम उपयोग, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल टिकाऊ उत्पादन प्रणाली, फसल एवं फसल के बाद के संचालन पर विस्तृत प्रस्ताव, डा. एस.के. मल्होत्रा, पूर्व कृषि आयुक्त द्वारा विकसित किया गया। इसके बाद यह सचिव, सीओएजी-एफएओ को सौंपा गया था। एफएओ, रोम के पौध उत्पादन एवं संरक्षण प्रभाग के निदेशक, डा. हंस ड्रेयर और उनकी टीम ने भारत के प्रस्ताव की जांच की। प्रस्ताव सही होने कारण कृषि समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के साथ एजेंडा प्रारूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए इसके सारांश के साथ एफएओ के प्रस्ताव प्रारूप में समाहित किया गया था। सीओएजी के सचिवालय ने पौष्टिक अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भारत के दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को अनुमोदित एजेंडा प्रस्ताव, टिप्पणी के साथ भेजा। इसके साथ भारत सरकार से मदों के प्रस्ताव को एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा पावर प्वाइंट मोड में इसकी जानकारी को प्रस्तुत करने की इच्छा जाहिर की गई थी। भारत सरकार के तत्कालीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने डा. एस.के. मल्होत्रा, कृषि

आयुक्त को एफएओ-सीओएजी बैठक में प्रस्ताव पेश करने के लिए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया और इस मद को 4 अक्टूबर, 2018 को एजेंडा संख्या-4.6 के तहत प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित किया गया था। श्री आर. रमेश, अटैशे (कृषि) भारतीय दूतावास, रोम द्वारा दूतावास की रिपोर्ट के अंश को, इसी रूप में, विदेश मंत्रालय को पुन: प्रस्तुत किया गया है। (रिपोर्ट की प्रति संलग्न)

एफएओ-सीओएजी (1-5 अक्टूबर 2018) ने अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष-2023 के अनुपालन के लिए भारत सरकार के प्रस्ताव की समीक्षा की तथा इस विचार के समर्थन के लिए एफएओ परिषद के 160वें सत्र (3-7, दिसंबर 2018) और इसके बाद में एफएओ सम्मेलन के 41वें सत्र (22-29, जून 2019) में सर्वसम्मति से अंगीकार करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष-2023 की घोषणा

एफएओ-सीओएजी, एफएओ काउंसिल, एफएओ सम्मेलन की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से भारत द्वारा प्रायोजित और 72 देशों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को अपनाया और वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष' घोषित किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम सहमति से 3 मार्च, 2021 को भारत द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के संकल्प-2023 को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, टी.एस. तिरुमूर्ति ने सभी सह-प्रायोजक: विशेष रूप से बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को उनके जोरदार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। 193 सदस्यीय, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पौष्टिक अनाजों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष घोषित करते हुए भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया है। यह संकल्प पौष्टिक अनाजों के जलवायु अनुकूल और पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके टिकाऊ उत्पादन के साथ खपत में वृद्धि के माध्यम से विविध, संतुलित और स्वस्थ आहार को समर्थन देने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। यह पौष्टिक अनाजों की विशाल आनुवंशिक विविधता और उत्पादन स्वीकृति प्रदान करने हेतु वातावरण की एक शृंखला के लिए उनकी अनुकूलन क्षमताओं को भी पहचानता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने प्रस्ताव पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने की पहल और उसके नेतृत्व के लिए भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं इसे सह-प्रायोजित करने वाले सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया। अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा, भारत पौष्टिक अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए अग्रणी होने पर सम्मानित महसूस कर रहा है। इसके वृहत उपभोग से पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के साथ किसानों का कल्याण होता है। उन्होंने कहा, यह कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्ट-अप समुदायों के लिए अनुसंधान और नवाचार के अवसर भी प्रदान करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष 2023 को वैश्विक स्तर पर मनाने के लिए भारतवर्ष विश्व प्रतिनिधित्व के लिए तैयार है और इस दिशा में बहुत सारे अग्रिम प्रयास भी कार्यशील हैं। ■





कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
GOVERNMENT OF INDIA

F.No. 11.11/2017 TC
14 August 2018

राधा मोहन सिंह
Radha Mohan Singh

प्रिय श्री जोस ग्रेजिआनो दा. सिल्वा,

आपको विदित होगा कि पौष्टिक अनाज अफ्रीका और एशिया के समुदायों के लिए प्रमुख खाद्यान्न रहा है, किंतु उनकी प्लेट से अब यह गायब होने लगा है। इसलिए वैश्विक स्तर पर इसकी मांग और खेती के क्षेत्रफल में लगातार कमी हो गई है। उच्च पोषक तत्वों से भरपूर होने और मोटापा, डायबिटीज जैसे वर्तमान जीवनशैली से संबंधित रोगों में बेहद उपयोगी होने के कारण, इन पौष्टिक अनाजों की विशेषकर छोटे किसानों और कृषक परिवारों के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रबंधन और अनुकूलनशीलता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका है। इसलिए इन न्यूट्रीसिरियल्स को सभी गरीब और अमीर एवं ग्रामीण या शहरी उपभोक्ताओं की खाद्य टोकरी तक पहुंचाने और इनका उत्पादन बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है।

इस संदर्भ में आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि भारतवर्ष 2018 को 'राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष' के रूप में मना रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में फसल प्रणालियों में सुधार कर इनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को हासिल करने में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है।

इस विषय पर अधिकाधिक वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत की ओर से आगामी किसी वर्ष को 'अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष' घोषित करने के लिए खाद्य कृषि संगठन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसकी प्रति आपके संदर्भ के लिए प्रेषित है। दिनांक 5 जुलाई 2018 को कृषि समिति की ब्यूरो बैठक में रखे जाने पर इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का भी समर्थन मिला है। आपके अवलोकन के लिए पौष्टिक अनाजों के बहुआयामी लाभों पर एक लघु प्रस्तुति भी संलग्न है।

अत: आपसे अनुरोध है कि रोम में 1-5 अक्टूबर 2018 को होने वाली कृषि समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को एजेंडा में शामिल करने की कृपा करें। सदस्य राष्ट्रों के समर्थन सहित खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इस प्रस्ताव को अपनाने से यह यूनजीए तक पहुंच सकेगा तथा आगामी किसी भी वर्ष को 'अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष' घोषित किया जा सकेगा। आपको विश्वासपात्र

Radhe Mohan Singh

(राधा मोहन सिंह)

कार्यालय: कमरा नम्बर 120, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, फोन: 23383370, 23782691, फैक्स: 23384129